

## THE JHARKHAND GAZETTE

# EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 446

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

#### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

-----

NOTIFICATION 29<sup>th</sup> June, 2017

#### NOTIFICATION No. 14 / 2017 State Tax (Rate)

**S.O-44- Dated- 29<sup>th</sup> June, 2017--** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

"Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution."

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

**K.K. Khandelwal,** Principal Secretary-cum-Commissioner

#### वाणिज्य-कर विभाग

\_\_\_\_\_

अधिसूचना 29 जून, 2017

### अधिसूचना संख्या 14/2017-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰-44- दिनांक- 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यकलाप या संव्यवहार जिसमें उन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में नियोजित किया गया है, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:-

संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से सेवा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं. वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> **के॰ के॰ खण्डेलवाल,** प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।